Sugar Board

+

*1026. SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE:

SHRI S. R. DAMANI:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Government has been feeling the need of concentrated efforts to boost up Sugar consumption in the country;

(b) if so, whether the Government will consider the advisability of having "Sugar Board" on the pattern of "Tea Board" or "Coffee Board' which can take up the responsibility of marketing as well as developing sugar consumption habits in the masses; and

(c) the reaction of the Government regarding the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a). Yes, Sir. In fact it was with the main intention of stimulating domestic consumption that sugar was decontrolled during 1978 and the objective has been achieved to a large extent in as much as the domestic consumption of sugar has gone upto 33.49 lakh tonnes (upto 22-4-1979) during the current season as against 24.53 lakh tonnes during the corresponding period last year.

(b) and (c). In view of the above trend in the consumption of sugar following decontrol, any other extra measure like setting up a Sugar Board for achieving the same purpose does not seem to be indicated.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: The per-capita consumption of sugar in the country is very low as compared to that in other countries. No concerted efforts have been so far made in the country to boost up sugar consumption especially in the rural areas. Therefore, my suggestion for setting up "Sugar Board" will go a long way in stabilising the sugar production and in helping the sugar industry. Why is it that the Government is not prepared to accept the suggestion?

The Minister has said in his reply:

"The domestic consumption of sugar has gone upto 33.49 lakh tonnes (upto 22-4-1979) during the current season as againset 24.53 lakh tonnes during the corresponding period last year."

Will he give us the break-up of this increase i.e., how much was the increase in the urban areas and how much in the rural areas? What would be the total production and consumption of sugar during the current season and the carry-over stock of sugar at the end of the season?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: First of all, I would like to say that the consumption of sweetening agents in our country is no less than the world average. Our sugar consumption appears to be low simply because in other countries, they do not consume gur and khandsari. If we take into account the production and consumption of gur and khandsari also....

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: I was asking about sugar consumption.

MR. SPEAKER: He is telling about the total consumption of sweetening agents.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: As far as the question, as to what part of it is going to the rural areas and what part is being consumed in the urban areas, is concerned, I have no precise information. But most of the additional consumption is going to the rural areas because it is there that formerly under the dual—pricing system, sugar was not available and now the consumption has gone up because it is freely available throughout the country. The estimated balance of sugar this year is likely to be 25 to 26 or may be 27 lakh tonnes.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: He had given the figure of estimated

balance. What would be the likely consumption of sugar during the current year? He has not given that. I would like to know whether any concerted efforts would be made to achieve a targt of say 72 lakh tonnes of sugar consumption during the year in the country.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: I did not follow the second part.

MR. SPEAKER: Whether you would make efforts to see that target of 72 lakh tonnes of sugar consumption is achieved.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Why should we? The consumption of sugar is satisfactory at the present level and we do not intend to make any special efforts for increasing the consumption because even this year, the consumption is likely to be equal to production. So, it is a good balance that we have achieved.

SHRI B. RACHAIAH: In view of the balance of nearly 27 lakh tonnes, which is available, will the Minister allow the export of increased sugar this year?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: We are already exporting upto the quota that is fixed for this country.

SHRI B. RACHAIAH: I want to know whether the quota can be enhanced.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: We will export further, if they want to.

SHRI B. VINODBHAI SHETH: The question was whether the Government is making concreted efforts to boost up sugar consumption in the country. Khandsari is a part and parcel of sugar. My question is whether they will boost up the production of khandsari in the country because khandsari industry is rural-oriented.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: It changes from year to year and it is not one of the organised industries. While we try to encourage production of 'khandasari' sugar, it is not entirely in our hands. For example, we have completely withdrawn the excise duty on 'khanasari'.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा है कि हम ने चीनी पर से कंट्रोल हटाया । उस समय चीनी 2 रु० 15 पैसे प्रति किलो यानी 215 रु० क्विंटल बिकती थी । आज चीनी का दाम 270, 280 रु० प्रति क्विंटल है और यह दाम दो महीनों में बढ़े हैं । इस का मूल कारण क्या है ? क्या आपने उद्योगपतियों को छूट दी है दाम बढ़ाने की ? यदि नहीं तो उन्होंने कैसे दाम बढ़ा दिये, क्या आप का कोई नियंत्रण नहीं है

श्री भानु प्रताप सिंह : पहली बात तो यह है कि जो 2 रु० 15 पैसे की बात कही जाती है वह केवल लैवी शुगर के लिये थी । सारे देश में चीनी के विक्रय का हम हिसाब लगायें तो उस का ऐवरेज 3 रु० 40 पैसे था और अभी जो आखिरी सप्ताह है उस का 2 रु० 78 पैसे है । हम ने जिस समय डी कंट्रोल किया था उस समय कहा था कि 2 रु० 75 पैसे लगभग इस का दाम होना चाहिये । तो जो अनुमान था उस में 2, 3 पैसे का ही अन्तर है, और इस का कारण यह है कि ट्रांसपोर्ट की कास्ट बढ़ गई है और कुछ राज्यों में चीनी मिल मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ायी गयी है । तो मैं समझता हूं कि जो हमारा अनुमान था, जिस लेविल पर हम चाहते थे उस लेविल पर आज भी चीनी बिक रही है । बीच में जरूर कम हो गई थी, लेकिन यदि वह कम ही बनी रहती तो फिर गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कीमत देने में कठिनाई होती ।

श्री रामधारी शास्त्री : इस बात को देखते हुए कि पिछले साल का भी गन्ने का दाम बकाया है काफी, और उन मिलों के जिम्मे भी बकाया है जिन को केन्द्रीय सरकार ने अपने कानून के अन्तर्गत इस साल लिया है । और पिछले साल चीनी के लिये समस्या इस देश में थी कि यह चीनी कैसे बिकेगी, और अब भी जब किसानों को दाम मिलने लगेगा तो उत्पादन बढ़ेगा । तो यह चढ़ते उतरते भाव के खतरे को टालने के लिये क्या मुनासिब नहीं है कि चाय और काफी बोर्ड की तरह सरकार कोई शुगर बोर्ड भी बनाये जो हमेशा इस की गतिविधियों पर ध्यान रखे और इस के समुचित विकास के लिये प्रयास करता रहे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह : अभी तो इस प्रकार का कोई विचार नहीं है । चाय या काफी मुख्य रूप से विदेशों में भेजनी पड़ती है इसलिये उन के लिये बोर्ड के संगठन की आवश्यकता है ।

जहां तक गन्ने के बकाये का सवाल है जो सरकार ने मिलों को टेक ओवर कर लिया है उन पर बकाया जो तीन इंस्टालमेंट्स में अदा करने की बात कही गई थी । आधे से ज्यादा अदा कर दिया गया है और बाकी शीघ्र ही अदा किया जायेगा ।

जहां तक प्राइवेट सैक्टर की मिलें हैं उन में बढ़ते हुए गन्ने के बकाया की बात है वह कार्यवाही शुरू कर दी गई है । जिस के ऊपर 10 प्रतिशत से अधिक बकाया है उन से फिर पूछा जा रहा है कि आप की मिल क्यों न टेक ओवर कर ली जाय ।

श्री उग्रसेन : मंत्री जी के उत्तर से संबंधित क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभी मिल ओनर्स ऐसोसियेशन ने उन के पास इस बात की शिकायत भेजी है कि हम ने गन्ने का दाम नहीं दिया है क्योंकि 400 करोड़ रु० का ही कर्जा मिला है, हमें 600 करोड़ का कर्जा दिलायें । और मंत्री जी ने अभी दो मिलें मेरे क्षेत्र में ली हैं, एक बेनालपुर चीनी मिल और दूसरी देवरिया शुगर मिल, तो थापर के जमाने में बेनालपुर चीनी मिल पर किसानों का 21 लाख रु० बकाया था और देवरिया पर 12 लाख रु० बकाया था जो कि बढ़ कर इन के जमाने में बेनालपुर पर 77 लाख रु० और देवरिया चीनी मिल पर 44 लाख रु० हो गया किसानों के गन्ने के दाम का बकाया । और मंत्री जी उधार चीनी खा रहे हैं और खिला रहे हैं । तो इस स्थिति को ठीक करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह : ये मिलें बाद में ली गई हैं । बैंकों से प्रबन्ध करने में थोड़ा समय लगता है । यह केवल हमारे मंत्रालय का ही कार्य नहीं है । इस बारे में बैंकिंग डिपार्टमेंट से भी सम्पर्क बना कर कार्यवाही करनी होती है । मिलों के जो पहले मालिक थे, बैंकों ने उन्हें एडवांस देना बन्द कर दिया था । अब सरकार ने उन्हें ले लिया है । अब हमारी इन्टरवेन्शन पर उन्हों ने सहमति दी है ।

श्री उग्रसेन : अब करवा दीजिए ।

श्री भानु प्रताप सिंह : वह तो होगा ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार की देख-रेख में जो मिलें हैं, उन पर जो बकाया है, वह देने का इन्तजाम किया जा रहा है । सरकार की देख-रेख में पिछले चार सालों से वे मिलें चल रही हैं । करंट सीजन में उन पर बकाया 50, 60, 70 लाख रुपये है । उस के मुताल्लिक मंत्री महोदय का क्या ख्याल है ? वह बकाया क्यों नहीं दिया जा रहा है ? मैं करंट सीजन की बात कर रही हूं, पिछले बकाया की नहीं ।

गन्ना किसानों को उन के गन्ने के दाम नहीं मिल रहे हैं । मंत्री महोदय को मालूम है कि खुले बाजार में 3–10 रुपये किलो के हिसाब से चीनी मिल रही है । कन्ज्यूमर्स को सही दाम पर चीनी नहीं मिल रही है, जिस के बारे में उन्हों ने वादा किया था । आखिर उनकी पालिसी किस के लिए है ? न किसान के लिए है, न कन्ज्यूमर्स के लिए है । तो क्या उन की पालिसी मिल-मालिकों के लिए है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : मालूम होता है कि माननीय सदस्या का विचार कुछ राजनीति से प्रभावित है : (व्यवधान) उन्हों ने कहा है कि कुछ मिल चार वर्ष से सरकार के नियंत्रण में हैं । पहले तो मैं इस का स्पष्टीकरण कर दूं कि वे चार वर्ष से सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं । शुगर अंडरटेकिंग्ज (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमेंट) एमेंडमेंट बिल को पास किये हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ है । वे मिलें हमारे नियंत्रण में अभी बहुत थोड़े समय से हैं । जो फैक्टरियां उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं, उन के लिए उन्हें 20 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था और उन्हों ने सारा बकाया साफ कर दिया है । जहां तक सरकारी मिलों का सम्बन्ध है, चाहे वे राज्य सरकार की हों अथवा केन्द्रीय सरकार की, अगर उन की तरफ बकाया की कोई धनराशि है, तो वह इस साल की है । जहां तक इस साल का सम्बन्ध है, अभी मिलें चल रही हैं । उस बकाया को साफ करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्या ने यह उठाया कि चीनी का दाम उन्हें 3–10 रुपये अदा करना पड़ रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली ही सारा देश नहीं है । दिल्ली में चीनी का मूल्य कुछ ज्यादा होता है । उस का मुख्य कारण यह है कि यहां के निवासी अच्छी किस्म की चीनी सी–30 खाते हैं, जिस की कीमत दस पैसे ज्यादा है । यहां 10, 11 रुपये प्रति क्विंटल आक्टराय ड्यूटी भी है । मेरे पास सारे देश की मंडियों के रिटेल बाजार भाव हैं । उन का औसत 2–78 रुपये है ।

श्री राम लाल राही : अभी मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उस के सम्बन्ध में मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । उन्हों ने कहा है कि हम ने खंडसारी पर से उत्पादन-शुल्क हटा दिया है। सरकार ने यह उत्पादन-शुल्क इस लिए हटाया था कि किसानों के गन्ने की अधिक खपत हो और उन को अच्छा मूल्य मिले । उन्हें विदित है कि गन्ने के काश्तकारों का गन्ना किस भाव पर लिया गया है–वह 3 रुपये से 5 रुपये के बीच में लिया गया है । इस बात को देखते हुए कि खंडसारी के मालिकों ने अधिक मुनाफा कमाया है, क्या मंत्री महोदय इस बात के औचित्य को स्वीकार करते हुए इस पर पुनर्विचार करेंगे कि खंडसारी पर टैक्स पुनः लगा दिया जाय ?

आप जानते हैं कि काश्तकार प्रति-एकड़ 50 मन बीज डाल कर गन्ना बोता है और उस का सट्टा 35 क्विंटल प्रति एकड़ का होता है । 50 मन बीज डाल कर गन्ना बोया जाता है और 35 क्विंटल प्रति-एकड़ उस का सट्टा होता है, क्या यह किसान के साथ न्याय है ? आप इस पर भी अपने विचार व्यक्त करेंगे और यह बतायेंगे कि अगर इस में गलती है तो क्या इस में कोई सुधार करने की बात आप सोच रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमान्, खांडसारी उद्योग का नियंत्रण राज्य सरकार करती है । राज्य सरकारों से परामर्श कर के और बहुत से माननीय सदस्यों से भी मशविरा करने के बाद खंडसारी पर से टैक्स हटाया गया था और इस आशा से हटाया गया था कि उस का लाभ

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 2(3)2
12. 9. 79

किसानों तक पहुंचेगा । अब वह आशा अगर नहीं पूरी करा सके तो उस की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है क्योंकि हम उस का बिल्कुल नियंत्रण नहीं करते हैं । लेकिन ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं पहुंचा हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि इधर जब से चीनी के मूल्य थोड़ा बढ़े हैं खंडसारी की यूनिटों ने काम काम करना शुरू कर दिया है । खांडसारी शुगर बनी है और उस के कारण गन्ने की खपत तेजी से हो सकी है जो शायद खेतों में खड़ा रह जाता । तो यह बिल्कुल निरर्थक नहीं हुआ है । उसका कुछ लाभ सामने आया है ।

दूसरी बांडिंग की बात कही गई । तो वह भी मैं कहना चाहता हूं कि फैक्टरियों के साथ किस तरह से बांडिंग इत्यादि होती है, इस से केन्द्रीय सरकार का कोई सरोकार नहीं है । यह राज्य सरकारें अपने यहां जैसा उचित समझती है करती हैं ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : माननीय मंत्री जी ने बताया कि देश में आवश्यकता के अनुसार चीनी का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में है । लेकिन इस के बावजूद चीनी का दाम कुछ न कुछ बढ़ता रहा है । तो क्या इसका कारण यह नहीं है कि आवश्यकता से अधिक चीनी का निर्यात किया जाता है और वह भी अच्छी क्वालिटी की चीनी कम दर पर निर्यात की जाती है ? मैं जानना चाहता हूं कि चीनी के निर्यात की दर और जो उपभोक्ताओं को चीनी मिलती है उस की दर में अन्तर कितना है और इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि आगे एक शुगर बोर्ड बना कर इस समस्या का निरन्तर समाधान करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन, चीनी के मूल्य पर निर्यात का कोई तत्काल और सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा है और निर्यात आवश्यक है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब यह कहा जाता है कि भाव बढ़ गए तो किस की तुलना में बढ़ गए ? अगर पहले जो भाव प्रचलित थे उस से तुलना करें तो भाव नहीं बढ़े हैं । हां, थोड़े समय पहले दो तीन महीने पहले जितने गिर गए थे और वह गिर इस लिये गए थे कि फैक्टरियों में आपस में बहुत जबर्दस्त कम्पीटीशन था, वह किसी तरह रुपया निकाल कर अपना भुगतान करना चाहते थे क्योंकि उन के ऊपर यह भय भी था कि उन की फैक्ट्री टेक ओवर कर ली जायेगी, इसलिए वे बेचने में तेजी दिखा रहे थे, वास्तव में जो भाव उस समय प्रचलित हो गए थे वह उचित नहीं थे, वह जरूरत से ज्यादा नीचे गिर गए थे और जैसा मैंने कहा सरकार का अपना अनुमान था कि भाव 2–75 के लगभग होना चाहिये और उसी के लगभग आज है । अब रहा यह कि जो हम ने उस समय अनुमान लगाया था 2–75 का उस में अगर आज कुछ चीजें बढ़ाई गई हैं जैसे ट्रान्सपोर्ट का खर्चा बढ़ गया या राज्य सरकारों ने चीनी मिल मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी तो उस का थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर पड़ेगा लेकिन वह अधिक नहीं है ।

Cooperative Farming

*1027. SHRI SUDHIR GHOSAL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have decided to develop cooperative farming for the poorer section of the peasantry; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

SHRI SUDHIR GHOSAL: In reply to my question whether Government have decided to develop cooperative farming for the poorer section of the peasantry, the hon. Minister has replied 'No, Sir'. Will the hon. Minister state why not?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: The main reason is that the small farmers who are expected to join the co-operative farm are not enthusiastic at all. Secondly, the results of co-operative farming are very discouraging. Their production per hectare and value of produce per hectare are dismally low.

SHRI SUDHIR GHOSAL: Why cannot Central Government instruct all State Governments including the Government of West Bengal to implement the legislation of consolidation of holdings, if any?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Yes, we are advising all the State Governments to go ahead with the work of consolidation of holdings.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Government said that they have not taken the decision. They have given answer to the first supplementary of my friend that farmers themselves are not willing and the results of